

एलआईसी आईपीओ-लोगों के विश्वास की बिक्री

13 फरवरी 2022 को सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करके सरकार एलआईसी आईपीओ के बहुत करीब पहुंच गई है। सरकार जब यह आम अवकाश वाले दिन शाम को करती है तो यह उसकी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के अन्त से पहले संसाधन जुटाने की हताशा को दर्शाता है। बताया गया है कि 10 रुपये अंकित मूल्य के 31.6 करोड़ से अधिक शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। यह एलआईसी में सरकार की 6325 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी का पांच प्रतिशत होगा। फ्री रिजर्व को हड़प कर और पिछले दो वर्षों के लाभांश को जब्त करके अंश पूंजी को 100 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया था। अमेरिकी बीमांकिक फर्म मिलिमन एडवाइजर्स ने एलआईसी के भारतीय एंबेडेड मूल्य का आकलन 539686 करोड़ रुपये किया है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए कौन सा गुणक सूत्र लागू किया जाएगा।

सेबी के पास दायर दस्तावेज में कहा गया है कि विनिवेश की पूरी राशि सरकार के पास जाएगी और एलआईसी को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऑफर फॉर सेल ने पात्र संस्थागत निवेशकों, विदेशी निवेशकों, घरेलू संस्थाओं और म्यूचुअल फंड्स के लिए इश्यू का 65 प्रतिशत आरक्षित रखा है। शेष 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए होगा, जिसमें से 10 प्रतिशत मौजूदा पॉलिसीधारकों के लिए और 5 प्रतिशत एलआईसी के मौजूदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। दस्तावेज में प्राइस बैंड का उल्लेख नहीं है और शायद संस्थागत और एंकर निवेशकों के साथ बातचीत के बाद यह तय किया जाएगा।

एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूर्ण गोपनीयता के साथ की गई है। कर्मचारियों और अभिकर्ता बल सहित हितधारकों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई। कर्मचारी संघटनों के साथ परामर्श करने के लिए वित्त मंत्री और एलआईसी अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र अनुत्तरित रह गए। सरकार संसद के अन्दर और बाहर एलआईसी आईपीओ पर चर्चा से बचना चाहती थी, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश लाने के लिए एलआईसी अधिनियम में संशोधन वित्त विधेयक के माध्यम से लाए गए थे। टेढ़ा यूनियनों ने इसे वित्त विधेयक से अलग करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री के समक्ष प्रतिवाद किया था और यह भी कहा था कि यदि सरकार चाहे तो वह अलग से संशोधन विधेयक ला सकती है। इस तरह के निर्णय से संसद को इस कदम के पक्ष और विपक्ष का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का अवसर मिलता और विधेयक को वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति के पास भेजने से सभी हितधारकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता। हालांकि, एक ऐसी सरकार से यह अपेक्षा कुछ ज्यादा ही थी जो लोकतन्त्र को खत्म करने और सभी स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने में लगी हो।

चूंकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, इसलिए इस तरह के गम्भीर संदेह है कि एलआईसी के मूल्य को कम करके आंका जा रहा है। यह एम्बेडेड मूल्य इस महान संस्था के वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाता है। बीमा कराने वाली जनता के बीच इसकी साख और स्वर्णमानकों वाले इसके अभिकर्ता बल के मूल्य को तो मापा ही नहीं

जा सकता है। इसकी विशाल अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन को लेकर भी संशय बना हुआ है। एलआईसी एक अनूठी संस्था है और दुनिया में कहीं भी ऐसा संस्थान मिलना मुश्किल है। इसको कुछ ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था जो लोगों के कल्याण और राष्ट्र के आर्थिक विकास से जुड़े हैं। इसकी संरचना की विशिष्टता ऐसी है जो इसके विशेषाधिकार प्राप्त पॉलिसीधारकों को शेयरधारकों से ऊपर रखती है। इस क्षेत्र को विदेशी और भारतीय दोनों तरह की निजी पूंजी के लिए खोलने के 22 साल बाद भी प्रीमियम आय में 64 प्रतिशत और पॉलिसियों की संख्या में 72 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जे के साथ इसने इसके बारे में तमाम बुरी भविष्यवाणी करने वालों को गलत साबित कर दिया। एआईआईईए इस बात पर हमेशा गर्व करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी दूसरी बीमा कम्पनी नहीं होगी जिसने बाजार पर इस तरह के प्रभुत्व का आनन्द लिया होगा जैसा एलआईसी ने लिया वो भी तब जब वह 23 निजी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, जिनमें से अधिकांश बड़े बैंकों द्वारा प्रवर्तित और बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित हैं। अनिच्छा से ही सही अब बड़े कारोबारियों द्वारा नियंत्रित मीडिया ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। एलआईसी इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कैसे चलाया जाना चाहिए। इसने न केवल नीतिगत धन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का ध्यान रखा बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी गौरवपूर्ण योगदान दिया। यह ग्रामीण इलाकों में भीतर तक बीमा का सन्देश ले गया। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रांड एलआईसी देश में सबसे लोकप्रिय और मूल्यवान ब्रांड है। यह संदेहास्पद है कि एलआईसी के मूल्य की गणना करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया होगा।

एआईआईईए यह तर्क देता रहा है कि विनिवेश, चाहे छोटा सा ही है, निजीकरण की दिशा में एक कदम है। एलआईसी जैसी संस्था का निजीकरण लोगों के जीवन और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एलआईसी का आईपीओ निश्चित रूप से इस संस्था की सामाजिक प्रतिबद्धता को खत्म कर देगा क्योंकि कारोबार का आधार बदलकर शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन पर केन्द्रित हो जाएगा। पॉलिसीधारकों के पक्ष में चल रहे अधिशेष वितरण के तरीके को 95 अनुपात 5 से बदल कर 90 अनुपात 10 में करना उन पॉलिसीधारकों के हितों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस बेहतरीन संस्था के विकास और विस्तार को वित्तपोषित किया है। यदि रेड हेरिंग दस्तावेज में एम्बेडेड मूल्य पर रिपोर्ट और अधिशेष वितरण के नियम में परिवर्तन से पहले और बाद में मूल्यांकन से आए अन्तर पर एक नजर डालें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भावी शेयरधारकों को मौजूदा और भविष्य के पॉलिसीधारकों की तुलना में विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। प्रॉस्पेक्टस स्वयं स्वीकार करता है कि इस परिवर्तन से एलआईसी की पॉलिसी का आकर्षण कम हो जाएगा और भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। दस्तावेज की एक करीबी जांच से पता चलता है कि आईपीओ के बाद, एलआईसी के व्यापार मॉडल को शेयरधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने वाले परिवर्तनों की तरफ जाना पड़ेगा। इस तरह के व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य मध्यम आय वाले और समाज के गरीब वर्गों, जिन्हें बीमा की सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है, की कीमत पर उच्च नेटवर्थ वाले ग्राहकों को लक्षित करना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा भी हो सकती है। वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से व्यवसायों की खरीद के नए तरीके और उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग से अभिकर्ता

बल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचेगा जिसने एलआईसी की वृद्धि और समृद्धि में सर्वाधिक योगदान दिया है। कारोबार का ऐसा ढांचा संस्थान में रोजगार को भी चुनौती देगा।

बीमा कर्मचारियों ने अपने उद्योग की रक्षा के लिए 1994 से एक अथक लड़ाई लड़ी है। भारी जन समर्थन की एकजुटता ने आन्दोलन को मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने की पिछली सरकारों की इच्छा को रोकने में मदद की। लेकिन वर्तमान सरकार जिसे बिना जवाबदेही वाले हानिकारक आर्थिक निर्णय लेने की विशेष योग्यता हासिल है, जनमत से बेपरवाह हैं। यह भारतीय लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करने वाली एलआईसी को सूचीबद्ध करने की जल्दबाजी दिखा रही है। यह समाज की भलाई की कीमत पर निजी व्यक्तियों के साथ इसके कार्यबल और पॉलिसीधारकों द्वारा बनाई गई सम्पदा का लाभ साझा करना चाहता है। इसने लोगों के विश्वास को ही बिक्री के लिए रख दिया है। एआईआईईए और बीमा कर्मचारी सरकार को यह आसान नहीं होने देंगे। बीमा कर्मचारी युद्ध के मैदान में हर कदम लड़ेंगे और आश्वस्त होंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय समाज के व्यापक हितों की रक्षा के लिए है। एआईआईईए ने एलआईसी कर्मचारियों को एलआईसी आईपीओ को सदस्यता के लिए खुलने वाले दिन एक दिवसीय हड़ताल कार्यवाही करते हुए मजबूत विरोध दर्ज करने का आह्वान किया है और उसके बाद एक निरन्तर संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इसने स्थिति की गम्भीरता को समझने और इस हड़ताल में शामिल होने के लिए अन्य यूनियनों से सम्पर्क किया है। एआईआईईए 28-29 मार्च 2022 को राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल में शामिल होकर मजदूर वर्ग के अन्य वर्गों के साथ एकजुटता को भी बढ़ाएगा। एआईआईईए के अभियान को बहुत समर्थन मिला है। कई राजनीतिक दलों और तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने इस कदम की आलोचना की है और केन्द्र सरकार से एलआईसी आईपीओ की प्रक्रिया को वापस करने की मांग की है। प्यूपिल्स कमीशन, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात अर्थशास्त्री, पत्रकार, शिक्षाविद और प्रमुख हस्तियां हैं, एलआईसी आईपीओ पर सरकार के फैसले के खिलाफ मजबूती से सामने आया है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने एलआईसी के आईपीओ को दो दिवसीय हड़ताल के लिए अभियान का अहम मुद्दा बनाया है। किसान संगठनों ने भी एकजुटता दिखाई है। लड़ाई शुरू हो गई है। आइए हम दृढ़ विश्वास के साथ इस लड़ाई में शामिल हों।

- सचिन जैन